- 20th Year
- Issue: 115
- 26.08.2026 (WEDNESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

घुसपैठियों और भगोड़े अपराधियों पर अब होगी डबल स्ट्राईक! अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश

नयी दिल्ली २५/०८ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि मल्टी-एजेंसी सेंटर के प्लेटफॉर्म पर उपलज्ध सूचनाओं का द्व आधारित विश्लेषण किया जाए और उससे उभरने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (स्ह्र्क्क) तैयार किए जाएं।

भगोड़े अपराधियों को देश में वापस लाकर उन्हें न्याय के कठघरे में पहुँचाने तथा देश से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के मोदी सरकार के अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब और सज्त निर्देश जारी कर दिये हैं। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह की ढिलाई को अस्वीकार्य बताते हुए अमित शाह ने सभी सुरक्षा और जांच एजेंसियों से घुसपैठ के खिलाफ कठोर कार्रवाई तेज करने को कहा है। साथ ही आतंकवाद, कट्टरपंथ, साइबर अपराध, नार्कोटिज्स और पाकिस्तान की छद्म युद्धनीति जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (द्व) और बेहतर एजेंसी समन्वय पर जोर दिया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सज्मेलन-2026 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि मल्टी-एजेंसी सेंटर (ख्र्ष्ट) के प्लेटफॉर्म पर उपलज्ध सूचनाओं का द्व आधारित विश्लेषण किया जाए और उससे उभरने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किए जाएं। उनका संदेश साफ है कि देश की सुरक्षा अब केवल पारंपरिक खतरों से निपटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक, खुफिया तंत्र और त्वरित कार्रवाई के जरिए दुश्मन की हर नई चाल का जवाब दिया जाएगा।

आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ भी अमित शाह ने निर्णायक रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने गृह मंत्रालय की क्क्र॥क्र योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण बढ़ाने, फरार अपराधियों को देश वापस लाकर मुकदमों में तेजी लाने और आवश्यकता पड़ने पर ट्रायल इन एज्सेंटिया यानी आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमे की कानूनी व्यवस्था के उपयोग को तेज करने के निर्देश दिए। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (क्क्र) के मामलों की जांच में भी अलग-अलग एजेंसियों के बजाय एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया।

हम आपको बता दें कि दो दिवसीय सज्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर मंथन हुआ। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों से निपटने की रणनीति, ख्र्ष्ट के जरिए खुफिया सूचनाओं का एकीकरण, विश्लेषण और ऑपरेशनल उपयोग, नशीले पदार्थों के खिलाफ विजन डॉज्यूमेंट, अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन, साइबर अपराध के खिलाफ नीति ढांचा तथा पाकिस्तान द्वारा छेड़े जा रहे प्रॉज्सी वॉर जैसे गंभीर विषय शामिल रहे।

सज्मेलन में आतंकवाद, साइबर अपराध, विज़ीय धोखाधड़ी, नार्कोटिज्स नेटवर्क, एन्क्रिप्टेड कज्युनिकेशन ऐप्स से पैदा हो रही चुनौतियां, घुसपैठ और अवैध आव्रजन पर भी विस्तृत चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही विमानन और बंदरगाह सुरक्षा तथा आतंकवादी और तस्करी गतिविधियों में शामिल भगोड़ों को वापस लाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने की रणनीति पर विचार किया गया। सज्मेलन के दूसरे दिन सुरक्षा एजेंसियों ने भविष्य के खतरों पर भी मंथन किया। इस दौरान सब-एरियल सिस्टम से पैदा हो रहे खतरों और उनके जवाबी उपायों, ज्लू इकोनॉमी की सुरक्षा, सूचना युद्ध और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव तथा देश के लिए मजबूत जैव-सुरक्षा ढांचे की जरूरत जैसे मुद्दों पर रणनीति तैयार की गयी। यह साफ संकेत है कि भारत अब सुरक्षा की लड़ाई केवल जमीन, सीमा और समुद्र तक सीमित नहीं मान रहा, बल्कि ड्रोन, डिजिटल स्पेस, सूचना तंत्र और जैविक खतरों तक फैले नए मोर्चों के लिए भी तैयारी तेज कर रहा है।

हम आपको बता दें कि हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित इस दो दिवसीय सज्मेलन में देशभर से 850 से अधिक अधिकारी और विशेषज्ञों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सज्मेलन में मौजूद रहे, जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक, जमीनी स्तर पर काम कर रहे युवा पुलिस अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ वर्चुअल माध्यम से जुड़े। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वर्ष 2021 से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सज्मेलन का आयोजन हर साल हाइब्रिड प्रारूप में किया जा रहा है। इसका मकसद जमीनी स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों से सीधे जूझ रहे अधिकारियों के अनुभव को विशेषज्ञों की सलाह के साथ जोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यावहारिक और प्रभावी समाधान तैयार करना है।

बहरहाल, अमित शाह के ताजा निर्देशों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने स्पष्ट रोडमैप रख दिया है। घुसपैठ पर कठोर प्रहार, अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन, आतंकियों और तस्करों जैसे भगोड़ों की देश वापसी, मुकदमों में तेजी, पाकिस्तान की छद्म युद्धनीति का जवाब और द्व आधारित खुफिया विश्लेषण तेज होगा। मोदी सरकार का संदेश साफ है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वालों, सीमा पार से घुसपैठ कराने वाले नेटवर्कों और कानून से भागने वाले अपराधियों के लिए अब बच निकलने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म की जाएगी।

मिसाइल निर्माण में बड़ी छलांग, ब्रह्मोस की रफ्तार से बढ़ेगा भारत-राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली २५/०८ (संवाददाता): रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेज़्नोलॉजी को भारतीय रक्षा कंपनियों को ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी है, ताकि देश के अंदर ही इनका उत्पादन किया जा सके। इस कदम का मकसद देश में ही मिसाइल बनाने की रज़्तार बढ़ाना, आयात पर भारत की निर्भरता कम करना और डिफेंस सप्लाई चेन में घरेलू कंपनियों (जिनमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी स्ल्स्ल्ब्न भी शामिल हैं) की भूमिका को बढ़ाना है।

मंत्रालय ने कहा कि टेज़्नोलॉजी ट्रांसफर से योग्य भारतीय उद्योगों को DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल सिस्टम का प्रोडज़्शन करने की इजाज़त मिलेगी, बशर्ते वे ज़रूरी योग्यता, सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करते हों। इस फ़ैसले को रक्षा क्षेत्र में सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इससे मिसाइल सिस्टम को डेवलपमेंट स्टेज से बड़े पैमाने पर प्रोडज़्शन (इंडस्ट्रियल-स्केल प्रोडज़्शन) तक ले जाने में मदद मिलेगी और साथ ही भारत के घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को भी मज़बूती मिलेगी।

मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मज़बूत करना और सप्लाई चेन में भारतीय स्ल्स्ल्ब्न और अन्य टेज़्नोलॉजी पार्टनर की भागीदारी के लिए मौके बनाना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत के पड़ोसी देशों में मिसाइल क्षमताओं को बड़े पैमाने पर निगरानी, संचार और सटीक हमले वाले नेटवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है। सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की जुलाई की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमताओं के तेज़ी से विस्तार पर ज़ोर दिया गया, खासकर चीन के साथ उसके सहयोग के ज़रिए। रिपोर्ट में कहा गया कि दशकों तक धीमी प्रगति के बाद, पाकिस्तान के %स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन ने 16 महीनों में छह सैटेलाइट लॉन्च किए। इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान अपनी स्वतंत्र अंतरिक्ष-आधारित निगरानी क्षमताओं को मज़बूत करने और सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी को ज़मीनी संचार प्रणालियों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

विष्णु देव साय ने 67 लाख महिलाओं को भेजे 631 करोड़

रायपुर २५/०८ (संवाददाता): छज़्ीसगढ़ के मुज़्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को प्रदेश की 67 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में 631 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, बालोद जिले के डौंडीलोहारा स्थित लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित महतारी वंदन सज़्मान समारोह में मुज़्यमंत्री ने प्रदेश के 67,28,918 हितग्राहियों के खातों में कुल 631.38 करोड़ से अधिक रुपये अंतरित किए। इन लाभार्थियों में बालोद जिले की 2.45 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। साय ने बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए कहा, ''हमारी माताओं-बहनों के चेहरे पर मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।'' मुज़्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सितंबर की किस्त भी 25 अगस्त को ही जारी करने का निर्णय लिया, ताकि त्योहार की खुशियां और बढ़ें। उन्होंने कहा, ''महतारी वंदन योजना केवल प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं बल्कि इसने महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नया भाव उत्पन्न किया है।'' साय ने कहा कि महिलाएं इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की शिक्षा, बचत और छोटे व्यवसाय जैसी जरूरतों के लिए कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के खातों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये अंतरित किए जा चुके हैं। मुज़्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

सीएम योगी का जेन जी कनेक्शन, नियुक्ति पत्र बांटने के बाद युवाओं के साथ ली सेल्फी

लखनऊ २५/०८ (संवाददाता): योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद युवाओं के साथ सेल्फी लीं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अपना संबोधन पूरा करने के बाद, सीएम योगी ने वहां मौजूद युवाओं से बातचीत की और उनके अनुरोध पर सेल्फी के लिए पोज़ दिया। इस कार्यक्रम के दौरान, मुज़्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार अगले छह महीनों में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य भर के युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगले छह महीनों में—कृपया ध्यान दें, अगले छह महीनों में—हम 1,00,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, जिन्हें हर हफ़्ते अलग-अलग बैच में बांटा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में सरकार ने उज़्र प्रदेश में 9,30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं और दावा किया कि इस दौरान किसी भी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया की आलोचना करते हुए, मुज़्यमंत्री योगी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलंदाज़ी से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन से ही 2017 से पहले के उस पैटर्न को तोड़ने का संकल्प लिया था, जिसमें भर्ती के विज्ञापन तो निकलते थे, लेकिन %चाचा-भतीजे की जोड़ी% और पूरा %महाभारत-शैली का कुनबा% वसूली के लिए पूरे राज्य में फैल जाता था। मुज़्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवाओं का चयन बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बिना भेदभाव के सबसे योग्य उज़्मीदवारों का चयन करते हैं, तो पूरे राज्य को इसका फ़ायदा मिलता है। राज्य उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है—और यह %डबल-इंजन% वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की पिछले नौ से साढ़े नौ वर्षों की एक बड़ी उपलज़्धि है। मुज़्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि सरकार अपराध के प्रति %जीरो-टॉलरेंस% की नीति अपना रही है और धोखाधड़ी व गड़बड़ी में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेगी।

बार-बार चुनाव विकास में बाधा, शिवराज सिंह चौहान बोले-एक देश, एक चुनाव से बदलेगी तस्वीर!

नयी दिल्ली २५/०८ (संवाददाता): केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को हरिद्वार में साधु-संतों से अपील की कि वे देश के विकास के लिए %एक देश, एक चुनाव% (ह्रहृश्व) की ज़रूरत के बारे में जागरूकता फैलाएं। %एक देश, एक चुनाव% पर साधु-संतों और धार्मिक नेताओं की एक सभा में शामिल होते हुए, चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित से जुड़ा है। चौहान ने साधु-संतों से आग्रह किया कि वे राजनीतिक सोच से ऊपर उठें और अपने प्रवचनों और सामाजिक प्रभाव के ज़रिए चुनाव में प्रस्तावित इस सुधार को आम लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव देश के विकास की रज़्तार को धीमा कर देते हैं, ज्योंकि ऐसे समय में प्रशासनिक मशीनरी, शिक्षक, पुलिस और सुरक्षा बल चुनावी कामों में व्यस्त हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से समय, पैसे और प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी, जिससे सरकार और प्रशासन विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे।देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर वंदे मातरम के महत्व को बताते हुए, उन्होंने साधु-संतों से इसके पूरे संस्करण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देश को किसी भी तरह के बंटवारे की ओर नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता सबसे ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, उज़्राखंड के मुज़्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज़ोर दिया कि एक साथ चुनाव कराने से जनता का पैसा बचेगा और उन्होंने साधु-संतों से इस मुद्दे पर समाज का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। इस मौके पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि देश में साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं।

सम्राट चौधरी ने शुरू किया विद्यार्थी सहयोग शिविर, 30 दिनों में होगा शिकायतों का निपटारा

वैशाली २५/०८ (संवाददाता): बिहार के मुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को वैशाली जिले के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की शिकायतों का प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

मुज़्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान के अनुसार, चौधरी ने 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत वैशाली के बिदुपुर स्थित बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की। बयान के मुताबिक, हर महीने के चौथे मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षाओं, छात्रावास, पेयजल, शौचालय, कैंटीन तथा विद्यार्थियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर शिकायतें तथा सुझाव सुने जाएंगे व उनका समाधान किया जाएगा। मुज़्यमंत्री ने कहा, ''विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है।विद्यार्थी सहयोग शिविर के माध्यम से छात्रों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिलेगा।'' उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का अधिकतम 30 दिनों के भीतर अंतिम निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और उनके समाधान की प्रभावी निगरानी भी की जाए। बयान के अनुसार, मुज़्यमंत्री ने कॉलेज के संकाय कक्ष में स्थापित सूचना एवं सहायता काउंटर का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों को उपलज़्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने कॉलेज में निर्बाध इंटरनेट कनेज़्टिविटी और निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों के अनुरोध पर मुज़्यमंत्री ने कॉलेज परिसर के निकट प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने का निर्देश दिया, ताकि छात्रों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बयान के अनुसार, यह शिविर हर महीने के चौथे मंगलवार को राज्य के शिक्षण संस्थानों में आयोजित किया जाएगा। बयान में बताया गया कि शिविर में विद्यार्थी अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सीधे संबंधित अधिकारियों तथा सरकार के समक्ष रख सकेंगे। शिकायतों के निस्तारण के लिए समयबद्ध व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' और हेल्पलाइन नंबर 1100 भी शुरू किया गया है। इन माध्यमों से छात्र-छात्राएं अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे और उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

मुज़्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना है। इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर छात्रों और अज़्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान देने की अपील की थी। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक की घटनाओं, परीक्षाओं के रद्द होने तथा परिणाम जारी करने में विलंब जैसे मुद्दे उठाते हुए कहा था कि इन परिस्थितियों से छात्रों और अज़्यर्थियों में व्यापक असंतोष और चिंता का माहौल है।

विविध समाचार

मैं सीनियर आइएएस हूँ, तुमने बदतमीजी की... महिला जज को फोन पर धमकाना पड़ा भारी, दुर्गा शक्ति नागपाल पर चलेगा अवमानना का केस!

नयी दिल्ली २५/०८ (संवाददाता): उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर आइएएस अधिकारी और देवीपाटन मंडल की कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत की महिला जज को फोन कर कथित रूप से प्रभावित करने और डराने-धमकाने के मामले को आपराधिक अवमानना के तहत सुनवाई के लिए संबंधित पीठ को सौंपने का निर्देश दिया है। जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़्वी की पीठ ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कथित टेलीफोनिक बातचीत की भाषा और लहजे से प्रथम दृष्टया यह साफ आभास होता है कि अदालत

के पीठासीन अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। अदालत ने इसे %चौंकाने वाला% करार दिया कि कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी लंबित मुकदमे के सिलसिले में सीधे जज से फोन पर संपर्क करे। अदालत ने इसे %चौंकाने वाला% भी बताया कि कोई पक्षकार/राज्य किसी लंबित मामले के संदर्भ में इस तरह के फोन कॉल के ज़रिए अदालत से संपर्क कर सकता है। ये टिप्पणियां 1997 के एक मुकदमे से जुड़ी ट्रांसफर अर्ज़ी पर की गईं, जो लगभग तीन दशकों से गोंडा के सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) के पास लंबित था। मामले का संक्षिप्त विवरण~ बेंच गोंडा के संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) से 1997 के मुकदमे को किसी अन्य सक्षम अदालत में ट्रांसफर करने की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी। 1997 से लंबित इस मुकदमे में सरकारी ज़मीन से जुड़ा विवाद शामिल था। 2018 में मुद्दे तय किए गए थे और मामला अभी सबूतों के चरण में है।

अदालत ने कहा कि देवीपाटन मंडल की कमिश्नर और सीनियर ढ्ढस् अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा सिविल जज को फोन करके उन पर डाला गया कथित दबाव, प्रथम दृष्टया न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और न्याय प्रशासन में बाधा डालता है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर आपराधिक अवमानना के तहत विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि मुज़्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से ज़रूरी निर्देश प्राप्त करने के बाद मामले को उचित अदालत के समक्ष लाया जाए। यह मामला देवीपाटन मंडल के कमिश्नर के नाम दर्ज नज़ूल ज़मीन के कई टुकड़ों से संबंधित था।

हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उपरोक्त को देखते हुए, यह अदालत प्रथम दृष्टया पाती है कि इस मामले में आपराधिक अवमानना ??से जुड़े मामलों को देखने वाली अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। माननीय मुज़्य न्यायाधीश/माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश से निर्देश लेने के बाद मामले को अवमानना मामलों को देखने वाली उचित अदालत के समक्ष रखा जाए।

चिराग पासवान ने आरक्षण को बताया संवैधानिक अधिकार

नयी दिल्ली २५/०८ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी अथॉरिटी खत्म नहीं कर सकती। उनका यह बयान जंतर-मंतर पर हुए %आरक्षण हटाओ आंदोलन% के जवाब में आया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने जाति-आधारित कोटा खत्म करने की मांग की थी। पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा कि ज़्या आरक्षण कोई ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ़ इसलिए खत्म किया जा सकता है ज़्योंकि किसी ने ऐसा कह दिया? यह एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है जो किसी को बांट दी जाए; यह एक संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो आरक्षण व्यवस्था में सुधार या समीक्षा करना चाहते हैं, और कहा कि वे इसकी ज़रूरत को नहीं समझते। पासवान ने दलितों के साथ हो रहे भेदभाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि उस मंच पर खड़गे के साथ जो हुआ, उसे देखिए। उनके जाने के बाद मंच को शुद्ध किया गया था, है ना? आज भी, एक दलित युवक को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है; एक दलित लड़के को शादी की बारात निकालने से रोका जाता है। जब बड़े नेता मंदिर जाते हैं, तो कभी-कभी परिसर को गंगाजल से धोया जाता है। तो, यह भेदभाव बना हुआ है, है ना? और ये वही अनुसूचित जातियां हैं जो छुआछूत की शिकार रही हैं। भेदभाव आज भी मौजूद है... मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब तक मैं यहां हूं और जब तक राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सरकार का हिस्सा हैं, मैं कभी भी इस व्यवस्था को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन% के तहत विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संज़्या में लोग जुटे और जाति-आधारित आरक्षण व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शिक्षा और रोज़गार में कोटा सामाजिक या जातिगत पहचान के बजाय पूरी तरह से आय के आधार पर तय किया जाए। उन्होंने एक परिवार, एक आरक्षण नीति और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (त्नष्ट) के 2026 के जाति-समानता निर्देशों को तुरंत वापस लेने की भी वकालत की।प्रदर्शन के जवाब में, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था। भारी भीड़ के बीच एहतियात के तौर पर सुरक्षाकर्मी तय विरोध स्थल पर मौजूद थे। %रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन-5.6 मिलियन फॉलोअर्स वाला एक आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज - ने %कॉकरोच जनता पार्टी% (ष्टछ्वक्क) जैसे ही विरोध प्रदर्शन जुटाने के तरीकों को अपनाकर तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की है और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है।

सावन के अंतिम सोमवार पर मधेपुरा के सिंगेश्वर मंदिर में मची भगदड़! बैरिकेड टूटने से आधा दर्जन लोग घायल

मधेपुरा २५/०८ (संवाददाता): बिहार के मधेपुरा जिले में स्थित ऐतिहासिक और आस्था के केंद्र बाबा सिंगेश्वरनाथ मंदिर में सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। तड़के से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। इसी दौरान मंदिर परिसर में क्षमता से अधिक भीड़ एकत्र होने और प्रवेश द्वार के पास अचानक एक सुरक्षा बैरिकेड के टूट जाने से भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस अप्रत्याशित घटना से मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जिसकी वजह से आधा दर्जन

से अधिक श्रद्धालु दबकर घायल हो गए। सुबह करीब 8 बजे मंदिर में भीड़ जुटना शुरू हुई। अचानक एक बैरिकेड टूट गया, जिससे भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए और वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। अधिकारियों के अनुसार, आधा दर्जन लोग घायल हुए। बाद में उन्हें इलाज के लिए मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया।पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें पुलिस अधीक्षक (स्क्क), जिलाधिकारी (ष्ठरू) अभिषेक रंजन, अनुमंडल दंडाधिकारी (स्ष्ठरू) और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं, मौके पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं और स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच, मंदिर ट्रस्ट समिति और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है। अधिकारी व्यवस्था बहाल करने के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले सोमवार को बिहार के लखीसराय जिले में अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से सात लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना भारी भीड़ के कारण हुई और बिजली का खंभा गिरने की अफवाह ने स्थिति को और खराब कर दिया। सावन के सोमवार भगवान शिव के लिए पवित्र माने जाते हैं। मृतकों की पहचान मनमाला देवी, रिंकू देवी, हेमलता देवी, ललिता देवी, सविता देवी, सरोज देवी और सावित्री देवी के रूप में हुई; ये सभी महिलाएं थीं।

बाद में, मुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख व्यक्त किया और घोषणा की कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। मुज़्यमंत्री ने ङ्ग (पहले ट्विटर) पर कहा, लखीसराय के अशोक धाम में हुई घटना दुखद और दिल दहला देने वाली है। इससे मुझे गहरा दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों को सही और तुरंत इलाज दिलाने के लिए प्रशासन को ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं।

जेएनयू वीसी की जातिवादी टिप्पणी पर बवाल, छात्रों ने मांगा इस्तीफा, कैंपस में भारी विरोध प्रदर्शन

नयी दिल्ली २५/०८ (संवाददाता):जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के कई स्टूडेंट्स ने मंगलवार को वाइस चांसलर शांति श्री धुलिपुडी पंडित के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पंडित ने यूजीसी रेगुलेशंस को इर्रेशनल और अनावश्यक बताते हुए कहा था कि उनके बयानों में जातिवादी बातें थीं। यह प्रोटेस्ट मेंबर्स द्वारा देर रात स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों पर किए गए हमलों की खबरों के बाद हुआ। एक बयान में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि जैसे मनुवाद की ताकतें सोशल जस्टिस के खिलाफ एक साथ हमला कर रही हैं, अंबेडकर की विरासत को जीतना होगा!

ङ्क्ष्ट के कमेंट्स का ज़िक्र करते हुए, AISA ने कहा, जेएनयू ङ्क्ष्ट, जिन्होंने पहले आरएसएस से अपने जुड़ाव पर बहुत गर्व जताया था, ने अपनी पार्टी लाइन को कन्फर्म किया और यूजीसी रेगुलेशंस को खारिज करते हुए कहा कि दलितों को %पर्म विक्टिमहुड% का नशा दिया गया था।्रढ्ढस्न इन गहरी ब्राह्मणवादी बातों की निंदा करता है और छ्वहृ ङ्क्ष्ट से पब्लिक में माफी मांगने और तुरंत इस्तीफे की मांग करता है।

एक ज़्लिक पर मिलेगी डाक सेवा, तकनीक के साथ जनसेवा के नए युग में प्रवेश कर रहा भारतीय डाक-ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली २५/०८ (संवाददाता):केंद्रीय संचार एवं पूर्वोज़र क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक देश की पुरानी और सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है, जो अब बदलते समय के साथ तकनीक और नवाचार को अपनाते हुए 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को नए स्वरूप में ढाल रहा है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया 'डाक मित्र' और, 'डाक सेवा' ऐप और 14 नवीनीकरण किए गए डाकघरों के शुभारंभ के अवसर पर डाक विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक के लिए केवल कुछ नई पहलों के शुभारंभ का दिन नहीं, बल्कि देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक की विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का अवसर है। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय डाक को सरल, तेज, सुलभ और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

उन्होंने कहा, आज नागरिक की अपेक्षा केवल यह नहीं है कि सरकारी सेवा उपलज़्ध हो, वह चाहता है कि सेवा उसके मोबाइल पर उपलज़्ध हो, उसकी उंगली के एक स्पर्श पर उपलज़्ध हो और वह भी तेज, सरल एवं पारदर्शी तरीके से हो। इस कड़ी में विभाग की पहल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी जिज़्मेदारी केवल पुरानी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को नागरिक के इर्द-गिर्द पुनः डिजाइन करना है। 'डाक मित्र' ऐप को डाक सेवकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह डाक, बैंकिंग, बीमा और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को एक ही ज़्लिक में उपलज़्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मई 2025 में इसके नए स्वरूप में आने के बाद 'डाक मित्र' ऐप अब 1.4 लाख ब्रांच पोस्ट ऑफिस में संचालित हो रहा है। इसके माध्यम से 2.45 करोड़ घरेलू स्पीड पोस्ट/पार्सल बुकिंग दर्ज की गई हैं और 15.09 करोड़ डाक वस्तुओं की डिलीवरी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इस पहल के माध्यम से 1,102 करोड़ के नए प्रीमियम और कुल ?5,431 करोड़ के प्रीमियम कलेज़्शन में योगदान हुआ है।

सिंधिया ने कहा कि पहले नागरिक को सेवा लेने के लिए डाकघर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब डाक सेवक सेवा लेकर नागरिक तक पहुंच रहा है। यही डिजिटल परिवर्तन की वास्तविक शक्ति है। आधार आधारित केवाईसी के माध्यम से बचत खाता खोलना, आधार बायोमेट्रिक से नकद निकासी और डिजिटल ई-केवाईसी जैसी सुविधाएं भी नागरिकों को अधिक सहज अनुभव प्रदान कर रही हैं।

'डाक सेवा' ऐप का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न डाक सेवाओं के लिए अलग-अलग माध्यमों पर निर्भरता से मुक्त कर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेवाएं उपलज़्ध कराना है।जून 2025 में शुरू हुए इसके पायलट के बाद ऐप को लगभग 10 लाख डाउनलोड मिल चुके हैं और इसके माध्यम से 91.34 लाख मेल एवं पार्सल आर्टिकल बुक किए जा चुके हैं।

'डाक सेवा' ऐप के माध्यम से नागरिक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं को ट्रैक कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट और पार्सल बुक कर सकते हैं। ई- मनी ऑर्डर जैसी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। शिकायत दर्ज कर उसका स्टेटस देख सकते हैं। नजदीकी डाकघर एवं पिन कोड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डाक शुल्क की गणना कर सकते हैं। विभिन्न लघु बचत योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्कद्यढ्ढ और क्रक्कद्यढ्ढ जैसी बीमा सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'डाक सेवा' ऐप 23 भारतीय भाषाओं में उपलज़्ध है। ऐप में यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलज़्ध है। एसबीआई ई पेय के माध्यम से ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बुकिंग प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं एकीकृत किया गया है।

डिजिटल के साथ भौतिक डाकघरों का भी कायाकल्प केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भौतिक डाकघर का महत्व कम हो गया है। डाकघर आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए विश्वास, मानवीय संपर्क और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी सोच के साथ देशभर में डाकघरों के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। 17 राज्यों में 40 डाकघरों को आधुनिक स्वरूप देने की पहचान की गई है, जिनमें 27 का कार्य पूरा हो चुका है और आज 14 डाकघरों का शुभारंभ किया गया।

आज जिन 14 डाकघरों का नवीनीकरण किया गया, इनमें पाटलिपुत्र (बिहार), वसंत कुंज (दिल्ली), सेज़्टर-56 गुरुग्राम (हरियाणा), काकुरगाची (कोलकाता), विदिशा और सांची (मध्य प्रदेश), शिलॉन्ग (मेघालय), कांदिवली पश्चिम (मुंबई), शंकर नगर एवं अयोध्या नगर (नागपुर), निराला नगर, गोमती नगर एवं इंदिरा नगर (लखनऊ) तथा प्रयागराज शामिल हैं। इन नए डाकघरों में आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐसा वातावरण विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को पारंपरिक डाकघर के विश्वास के साथ आधुनिक सेवा केंद्र की सुविधा भी मिल सके।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक केवल अपनी सेवाओं के विस्तार और डिजिटल आधुनिकीकरण की दिशा में ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि आर्थिक रूप से भी लगातार सशक्त हो रहा है। विज़ वर्ष 2024-25 में भारतीय डाक का राजस्व लगभग ?13,218 करोड़ रहा, जो विज़ वर्ष 2025-26 में बढ़कर ?15,296 करोड़ हो गया है। यह लगभग 16त्न की वृद्धि है। विज़ वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारतीय डाक ने 4,008.95 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक तिमाही राजस्व दर्ज किया।

पहली बार किसी एक तिमाही में ?4,000 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए साल-दर-साल लगभग 22त्न की वृद्धि दर्ज की गई। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय डाक अपनी विशाल पहुंच, नागरिकों के विश्वास और आधुनिक तकनीक के बल पर एक आर्थिक रूप से अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार संस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक की वास्तविक सफलता केवल ऐप के डाउनलोड या नए डाकघरों की संज़्या से नहीं मापी जाएगी। इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि इन पहलों से हमारे डाक कर्मचारियों का काम कितना आसान हुआ और देश के नागरिकों के लिए सेवाएं कितनी तेज, सरल, सुलभ और पारदर्शी बनीं। उन्होंने कहा, 卐पुराना भरोसा, नई तकनीक; वही अपनापन, नई गति, यही नया भारतीय डाक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप भारतीय डाक को आधुनिक, विश्वसनीय और तकनीक-सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है। देश के अंतिम छोर तक पहुंच और नागरिकों के साथ सीधा मानवीय जुड़ाव भारतीय डाक की सबसे बड़ी ताकत है, और अब तकनीक इस ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेज़्मासानी, डाक विभाग के सचिव सुब्रत दास, डाक महानिदेशक जितेंद्र गुप्ता सहित 8 राज्यों से जुड़े जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संज़्या में डाककर्मी उपस्थित रहे।

विविध समाचार

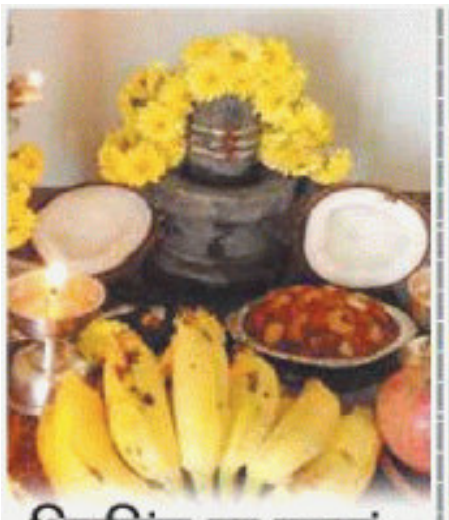

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये पांच अनाज, घर में आएगी सुख-समृद्धि

हिन्दू धर्म में शिवलिंग पूजा का बहुत महत्व है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, पुष्प, धतूरा, बेलपत्र आदि समेत कई चीजें चढ़ाई जाती हैं। इन्ही में से एक है शिवा मुट्ठी जिसमें पांच प्रकार के अनाज शिवलिंग पर अर्पित करने का खास विधान है। आइये जानते हैं कि कौन से 5 तरह के अनाज शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए।

शिवलिंग पर चढ़ाएं अक्षत

- शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है।
- चावल चढ़ाने से धन (धन लाभ के उपाय) से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।
- चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है।
- तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती है।
- ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए नहीं।

शिवलिंग पर चढ़ाएं अरहर दाल

- शिवजी को एक मुट्ठी गेहू चढ़ाने से सुख मिलते है।
- जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है।
- पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते है।
- पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है।

शिवलिंग पर चढ़ाएं काले तिल

- शिवलिंग पर काले तिल (काले तिल के उपाय) चढ़ाना लाभकारी माना जाता है।
- काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है।
- काले तिल चढ़ाने से पितरो का आशीर्वाद मिलता है।
- राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है।

शिवलिंग पर चढ़ाएं गेहूं

- शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसरिक सुख मिलते है।
- मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है।
- इसके अलावा, संतान सुख की प्राप्ति होती है।
- शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है।
- वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए।

शिवलिंग पर चढ़ाएं मूंग दाल

- शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है।
- किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती है।
- काम सफलता के साथ पूरा होता है। उसका लाभ मिलता है।

आखिर क्यों सबसे अनोखा है भगवान शिव का परिवार?

श्रावण मास विशेष: आखिर क्यों सबसे अनोखा है भगवान शिव का परिवार? श्रावण (सावन) मास भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में केवल महादेव की ही नहीं, बल्कि उनके पूरे दिव्य परिवार (शिव परिवार) की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और संतुलन बना रहता है। शिव परिवार हमें जीवन जीने के कई गूढ़ और व्यावहारिक संदेश देता है। आइए जानते है शिव परिवार से जुड़ी खास और अद्भुत बातें।

परम सामंजस्य का अद्भुत प्रतीक (विरोधी स्वभावों का मेल)

शिव परिवार विरोधाभासों के बावजूद अद्भुत तालमेल का सबसे बड़ा उदाहरण है।
शिव-पार्वती: शिवजी का वाहन बैल (नंदी) है, तो माता पार्वती का शेर।
गणेश जी: गणेश जी का वाहन मूसक (चूहा) है, तो शिव जी के गले में सर्प (सांप)।
कार्तिकेय: कार्तिकेय जी का वाहन मयूर (मोर) है, जो सांप का शत्रु है।
अशोक सुंदरी: कमल पर विराजमान।
खासियत: प्रकृति के नियम के अनुसार ये सभी एक-दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव दरबार में सभी शांतिपूर्वक और मिलकर रहते हैं। यह सीख देता है कि विचारों में मतभेद होने पर भी परिवार में प्रेम और एकता बनी रह सकती है।

अर्धनारीश्वर स्वरूप: स्त्री-पुरुष समानता

महादेव और माता पार्वती का 'अर्धनारीश्वर' रूप यह संदेश देता है कि सृष्टि के संचालन में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका और शक्ति बराबर है। एक के बिना दूसरा अधूरा है।

प्रथम पूज्य गणेश जी का संदेश

शिव-पार्वती के कनिष्ठ पुत्र श्री गणेश बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता के प्रतीक हैं। जब उनसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा गया, तो उन्होंने अपने माता-पिता की परिक्रमा की। यह सिखाता है कि माता-पिता का स्थान संसार में सबसे ऊपर है।

सेनापति कार्तिकेय जी: अनुशासन और नेतृत्व

शिव-पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। वे असीम साहस, अनुशासन, नेतृत्व और बुराई के विनाश का प्रतीक हैं। दक्षिण भारत में उन्हें 'मुरुगन स्वामी' के रूप में पूजा जाता है।

भगवान शिव की पुत्रियां

पौराणिक मान्यताओं (जैसे पद्म पुराण) के अनुसार, शिव-पार्वती केवल गणेश और कार्तिकेय के ही नहीं, बल्कि तीन पुत्रियों के भी पिता हैं- अशोक सुंदरी, मनसा देवी और ज्योति (ज्वालामुखी)। अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष से हुआ था। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा सौ रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के पांच पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके पांच पुत्रों का नाम था- 1. पुरु, 2. यदु, 3. तुर्वस, 4. अनु और 5. द्रुह्यु। इन्हें वेदों में पंचनद कहा गया है।

नंदी जी: भक्ति और अटूट धैर्य का प्रतीक

भगवान शिव के वाहन नंदी (बैल) केवल एक पशु नहीं, बल्कि परम भक्त और शिवगणों के अध्यक्ष हैं। मंदिर में नंदी की नजर हमेशा शिवलिंग पर टिकी होती है, जो अटूट ध्यान, भक्ति और धैर्य का संदेश देती है।

प्रकृति और पर्यावरण से गहरा जुड़ाव

शिव परिवार का हर सदस्य प्रकृति का रक्षक है। शिव जी स्वयं जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और गले में नाग धारण करते हैं। यह पूरा परिवार हमें प्रकृति, पशु-पक्षी और पर्यावरण की रक्षा व सम्मान करना सिखाता है।

संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों का संगम

शिव परिवार की पूजा करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त होते हैं। जहां शिव जी वैराग्य के स्वामी हैं, वहीं माता अन्नपूर्णा (पार्वती जी) धन-धान्य और समृद्धि की देवी हैं।

सावन में शिव परिवार पूजा का विशेष महत्व

सावन के महीने में केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ-साथ यदि पूरे शिव परिवार का अभिषेक और पूजन किया जाए, तो पारिवारिक कलह (झगड़े) दूर होते हैं और घर में सुख-शांति आती है।

आदर्श और सुखी परिवार का मापदंड

भारतीय संस्कृति में किसी भी परिवार को एकजुट, खुशहाल और आदर्श बनाने के लिए 'शिव परिवार' की उपमा दी जाती है। यह परिवार सिखाता है कि कम साधनों, सादगी और प्रेम के साथ कैसे एक सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है।

शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है या बेलपत्र?

बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। वहीं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शिव के अभिषेक का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते है कि शिवलिंग पर इन दोनों में से सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाना भगवान शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके पीछे गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व छिपा है। माना जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र की तीन पत्तियां त्रिदेवों का प्रतीक मानी जाती है और शिव पुराण के अनुसार ये शिव के त्रिशूल और उनकी तीन आंखों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। बेलपत्र को शीतलता प्रदान करने वाला भी माना जाता है। वहीं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शिव के अभिषेक का एक अभिन्न हिस्सा है। जल सृष्टि का आधार है और जीवन का प्रतीक भी। यह शिव के शांत और कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पूजन बिना जल और बेलपत्र के अधूरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर इन दोनों में से सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए।

शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं या बेलपत्र?

- धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से, शिवलिंग पर पूजा का एक निश्चित क्रम होता है और यह क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस क्रम का पालन करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा के दौरान सबसे पहले जल ही चढ़ाया जाता है। यह एक सर्वमान्य नियम है जिसका उल्लेख शिवपुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है।
- भगवान शिव का अभिषेक सबसे पहले शुद्ध जल से किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जलाभिषेक शिव जी को शीतलता प्रदान करता है जल उनके शांत और सौम्य स्वरूप को दर्शाता है और भक्तों के मन को भी शांति प्रदान करता है। पूजा की शुरुआत हमेशा शुद्धिकरण से होती है। जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे स्वच्छ और पवित्र किया जाता है।
- जलाभिषेक सबसे पहले इसलिए किया जाता है अन्य पूजन सामग्री को अर्पित किया जा सके। जल जीवन का आधार है और सृष्टि में हर जीव को पोषित करता है। शिव को महादेव कहा जाता है और जल चढ़ाकर हम जीवन की निरंतरता और शिव की पोषक शक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शिव पुराण और रुद्र संहिता में यह बताया गया है कि शिवलिंग का अभिषेक पहले गंगाजल या शुद्ध जल से करना चाहिए।
- शिवलिंग का सबसे पहले जलाभिषेक करने के बाद दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद फिर से गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है और फिर इसके बाद बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र के बाद फूल, धतूरा, भांग आदि अन्य पूजन सामग्री शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। आगे से आप भी शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाए फिर बेलपत्र अर्पित करें।

श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 2026

तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण और पूर्ण पूजन विधान

भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा और संतान सुख की कामना के लिए रखा जाने वाला श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत इस वर्ष 23 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। वैष्णव परंपरा में इसे 'पवित्रोपना एकादशी' या 'पवित्र एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। इसका पारण 24 अगस्त को होगा।

तिथि एवं पारण का समय

एकादशी तिथि प्रारंभ: 23 अगस्त 2026 को रात 02:00 बजे
एकादशी तिथि समाप्त: 24 अगस्त 2026 को तड़के 04:18 बजे

पूजा मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:51 से 05:36 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:16 से 01:06
गोधूलि मुहूर्त : शाम 07:01 से 07:23 तक।
व्रत की तिथि: 23 अगस्त 2026
पारण (व्रत खोलने) की तिथि: 24 अगस्त 2026
पारण का शुभ मुहूर्त: 24 अगस्त को दोपहर 01:57 बजे से शाम 04:28 बजे तक
हरि वासर समाप्ति का समय: 24 अगस्त को सुबह 10:49 बजे

पुत्रदा एकादशी का महत्व और फायदा

- वर्ष में दो बार पुत्रदा एकादशी आती है- पहली पौष माह में और दूसरी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में।
- उत्तर भारत में पौष माह की एकादशी का विशेष महत्व है, जबकि अन्य क्षेत्रों में श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी अत्यधिक श्रद्धा के साथ मनाई जाती है।
- सनातन परंपरा में संतान (विशेषकर पुत्र) द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कारों और श्राद्ध कर्म को आत्मा की तृप्ति और मुक्ति का मार्ग माना गया है। जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त करने में बाधा आ रही हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है।

पूजा एवं व्रत की सरल विधि

- **सुबह की शुरुआत:** सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
- **दीप प्रज्वलन:** भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें।
- **पूजन सामग्री:** पूजा में तुलसी पत्र, मौसमी फल और तिल विशेष रूप से अर्पित करें।
- **व्रत का नियम:** दिनभर निराहार रहें। शाम की आरती व पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं।
- **विशेष पाठ:** पूजा के दौरान 'विष्णुसहस्रनाम' का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है।
- **रात्रि जागरण:** एकादशी की रात सोएं नहीं, बल्कि प्रभु के भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करें।
- **दान व पारण:** अगले दिन (द्वादशी तिथि को) किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान-दक्षिणा दें और फिर शुभ मुहूर्त में स्वयं पारण करके व्रत पूर्ण करें।

कलिंग समाचार

संपादकीय

राहुल गांधी पर भाजपा का नया वार

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भाजपा का डर अब खुलकर सामने आने लगा है। बुधवार को राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह अमेरिका से हुए व्यापार समझौते और एपस्टीन फाइल्स पर मोदी सरकार को घेरा, उसके बाद उनके भाषण के कई हिस्से सदन की कार्रवाई से निकाल दिए गए। इसके बाद भी राहुल गांधी का सामना भाजपा नहीं कर पा रही है तो अब उन्हें संसद से बाहर करने की कोशिश करने लगी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को संसद में और संसद के बाहर कहा था कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। लेकिन गुरुवार को भाजपा ने सिर्फ लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। समझा जाता है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखे जाने पर भाजपा को अपने सहयोगी दलों से समर्थन की उ मीद नहीं थी। दूसरा डर यह था कि इस पर संसद में बहस के दौरान फिर केंद्र बिंदु राहुल गांधी ही बनते। और मोदी सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी पर बहस केंद्रित हो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने एक ठोस प्रस्ताव पेश किया है जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि वे कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआईडी से जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं, और भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। मैंने मांग की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। अपने डर को छिपाने के लिए नरेन्द्र मोदी ने निशिकांत दुबे को आगे किया है, हालांकि इस नोटिस के बाद भाजपा को यह साबित भी करना होगा कि जिन फाउंडेशन्स या देशों का नाम लिया गया है, वे किस तरह देश विरोधी हैं और राहुल से उनके क्या संबंध हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने और संसद सदस्यता खत्म करने का यह नोटिस उस समय दिया गया जब मोदी सरकार को ही यह साबित करना है कि एपस्टीन फाइल्स मामले में वह बेदाग हैं। क्योंकि नरेन्द्र मोदी, उनके केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, श्री मोदी के करीबी कारोबारी अनिल अंबानी जैसे लोगों के नाम इस कु यात मामले में आए हैं। ऐसे में केवल मुंहजबानी सफाई पेश करने से कुछ नहीं होगा। बल्कि ठोस सबूतों के साथ साबित करना होगा कि मानव तस्करी, यौन शोषण और मानवता को तार–तार करने वाले न जाने कितने घिनौने अपराधों से जुड़े इस मामले में किसी तरह भी मोदी सरकार का कोई संबंध नहीं है। हम यह बात पहले भी लिख चुके हैं कि इस मामले में दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं। किसी पर अपराध साबित हुआ या न हुआ हो, केवल एपस्टीन फाइल्स में नाम आने पर ही लोगों को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका में भी इस पर ट्रंप के विरोधी नेता सवाल कर रहे हैं और उन्हें सवाल करने दिया जा रहा है। मगर भारत में भाजपा को बचाने के लिए एपस्टीन फाइल्स का नाम लेना ही गुनाह की तरह दिखाया जा रहा है। बुधवार को जब संसद के भीतर राहुल गांधी को इस मामले में बोलने से रोका गया तो उन्होंने बाहर आकर अपने आरोपों को दोहराया। जिसके बाद केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। हालांकि वे चाहते तो जब से उनका नाम इस मुद्दे पर आया, तभी खुलकर सारी बातें बता सकते थे। लेकिन दबाने–छिपाने की इस प्रवृत्ति से ही शक गहराता है। बहरहाल, हरदीप सिंह पुरी ने माना कि उनकी मुलाकात कु यात अपराधी जेफ्री एपस्टीन से तीन–चार बार हुई थी। यानी राहुल गांधी ने संसद के भीतर जो कुछ कहा, उसे खुद हरदीप पुरी ने सत्यापित कर दिया है। इसके बाद उन पर क्या आरोप लगते हैं और कितने साबित होते हैं, ये तो बाद की बात है, सबसे पहले उन्हें नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार की डिक्शनरी में शायद नैतिकता शब्द है ही नहीं, इसलिए उसके आधार पर इस्तीफे भी नहीं होते। पत्रकारों को अपनी बात बताते हुए हरदीप पुरी ने कुछ बड़ी गलतियां कर दीं। एक तो उन्होंने कहा कि एपस्टीन पर कुछ कम उम्र की लड़कियों के शोषण का आरोप था, जबकि सच यह है कि इस मामले में उसे सजा भी हो चुकी थी। दूसरी बात कम उम्र की लड़कियों को ही बच्चियां कहा जाता है और यह बच्चियों की तस्करी, या उनसे दुष्कर्म बेहद गंभीर अपराध है।

भारत को कमजोर करने वाला अमेरिकी व्यापार समझौता

जगदीश रत्तनानी

अब जब भारत ने एक खिड़की खोल दी है तो डेयरी के मामले में अमेरिकी दबाव दूर नहीं होगा बल्कि समय के साथ और बढ़ने की संभावना है। इस आलोक में व्यापार समझौते में यह बयान कि, भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए लंबे समय से चली आ रही गैर–टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए भी सहमत है%, उस जाल की प्रकृति को इंगित करता है जिसमें भारत फंसता चला गया है।

आप इसे किसी भी तरह से घुमा–फिरा कर देंखे, यह स्पष्ट है कि व्यापार समझौते के बदले में अमेरिका के आदेशों के आगे भारत झुक गया है। यह भारत पर दंडात्मक टैरिफ को तो कम करता है लेकिन देश के दीर्घकालिक हितों को भी दूर करता है। इसके साथ ही लंबे समय से भारत के नीति ढांचे का केंद्रबिंदु रहे बहुप्रतीक्षित रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करता है। यह सच है कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार के संबंध में अंतरिम समझौते के बारे में सारे विवरण ज्ञात नहीं है लेकिन जो कुछ भी मालूम है– जिसमें सौदे के आसपास की परिस्थितियां, इसकी घोषणा का तरीका, संयुक्त बयान की भाषा और व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश शामिल हैं, इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत ने कुछ लंबे समय से चले आ रहे रुख को बदल दिया है और उस हद तक यह दो बराबर के देशों के बीच का समझौता नहीं है।

आपसी सहमति से जारी बयान का समय देखने पर पता चलता है कि अमेरिका साधारण शिष्टाचार पालने की तकलीफ भी नहीं उठाता। ट्रंप ने दोनों देशों द्वारा 6–7 फरवरी को आधिकारिक रिलीज से कुछ दिन पहले दो फरवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर व्यापक समझौते की घोषणा की थी।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा जारी संयुक्त बयान में भारत सरकार की घोषणा पर 7 फरवरी, सुबह 4.29 बजे टाइम स्टै प है जो एक अपरंपरागत समय है जिसे अमेरिकी टाईमज़ोन के अमेरिकी नेतृत्व वाली घोषणा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू ने कहा था कि %जब दुनिया सोएगी, तो भारत स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा% तो हम कह सकते हैं कि यह समझौता स्वतंत्रता और आदर्शवाद की उस सुबह के शाब्दिक और रूपक के उलटफेर को चिह्नित करता है क्योंकि जब भारत सो रहा था तब अमेरिका ने एक ऐसा समझौता किया जो भारत के व्यापारिक भागीदार और उस हद तक इसकी स्वतंत्रता, लक्ष्यों, अपनी प्राथमिकताओं को तय करने के अधिकार को छीन लेता है।

फिर भी, राजनयिक बारीकियों के बिना देंखे तो ट्र प और अमेरिकी प्रशासन की घोषणा का समय केवल एक गहरे नुकसान की सतही परेशानियों को चिह्नित करते हैं जिसे भारत को समय के साथ स्वीकार करना होगा। अमेरिका के साथ कठिन शर्तों पर की गई गलबहियां, विशेष रूप से खाद्य और कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक दीर्घकालिक पारिस्थितिकी–प्रणाली परिवर्तन का जोखिम उठाता है जो अपरिवर्तनीय हो सकता है और भारत को एक ऐसे रास्ते पर चलने को मजबूर करता है जो देश को बहुत असहज कर देगा। जो कुछ भी हो रहा है उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन भी सहज नहीं होंगे।

आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के बयान से देखा जा सकता है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) से संबंधित उत्पादों के लिए देश में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं खुलना चाहिए। जबरन सौदा करने की ट्र पवादी शैली और अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट के तरीके समय के साथ बीत सकते हैं लेकिन इस व्यापार समझौते के निहितार्थ लंबे समय बाद भी भारत के लिए एक कीमत तय करते रहेंगे। अल्पावधि लाभ के लिए किया गया समझौता अनिवार्य रूप से लंबी अवधि के लिए नुकसानदेह होता है।

ध्यान दें कि समझौते में शामिल न किए गये दूध के आयात के खिलाफ़ भारतीय नीति को अमेरिका विदेश व्यापार की राह में बाधा के रूप में देखता है। भारतीय विचार में डेयरी केवल उन जानवरों से होनी चाहिए जिन्हें रक्त युक्त पदार्थों वाला भोजन नहीं दिया जाता या जुगाली करने वाले अथवा सूअर के आंतरिक अंगों या ऊतकों से युक्त आहार नहीं दिया जाता है लेकिन अमेरिका का मानना है कि इस दृष्टिकोण में स्पष्ट पशु स्वास्थ्य या मानव स्वास्थ्य औचित्य का अभाव है।

अमेरिकी आयात के लिए कृषि क्षेत्र को खोलने का किसान समूहों ने विरोध किया है जिस पर देश को आश्वासन दिया गया है कि भारत के किसानों, एमएसएमई क्षेत्र, डेयरी या हथकरघा और हस्तशिल्प के हितों को नए व्यापार समझौते के तहत संरक्षित किया जाएगा और सौदे के एक हिस्से के रूप में कोई भी जीएम फसल भारत में प्रवेश नहीं करेगी लेकिन इस बात पर विचार करें कि नो–जीएम आयात का दावा एक पतले धागे से जुड़ा है– उदाहरणार्थ, ड्रायड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी–मक्का, चावल या गेहूं से एथेनॉल के उत्पादन के बाद बचा हुआ एक प्रमुख उप–उत्पाद है। यह पशु आहार, विशेषकर गायों और पोल्ट्री के लिए प्रोटीन, वसा और फाइबर का एक पौष्टिक व कम लागत वाला स्रोत है।

इस सूखे चारे का उपयोग पशुओं की उत्पादकता और ऊर्जा के लिए किया जाता है)। घोषणा के अनुसार व्यापार समझौते में पहले नंबर पर शामिल डीडीजी के अनाज या पशु आहार ज्यादातर जीएम फसल से आते हैं।

डीडीजी पशु फीड में पोषण मूल्य जोड़ता है लेकिन क्या यह दावा किया जा सकता है कि भारी प्रसंस्करण के बाद मकई से जो इथेनॉल निकाला जाता है उससे क्या जीएम गुणवत्ता मिटा दी जाती है? इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि प्रसंस्करण में ट्रांसजेनिक प्रकृति को समाप्त कर दिया गया है। डीडीजी का उपयोग मवेशियों, डेयरी गायों, सूअर और कुछ पोल्ट्री को खिलाने में किया जाता है जो डेयरी शृंखला में प्रवेश करने के लिए जीएम–लिंक्ड उत्पाद के लिए एक मार्ग खोलता है। इसके अलावा अगर यह भारत के लिए रेड लाइन नहीं है तो भारत अन्य बिंदुओं पर कब तक टिके रह सकता है?

उदाहरण के लिए डेयरी, जिस पर अमेरिका डीडीजी की तरह जोर दे रहा है? ध्यान दें कि समझौते में शामिल न किए गये दूध के आयात के खिलाफ़ भारतीय नीति को अमेरिका विदेश व्यापार की राह में बाधा के रूप में देखता है।

भारतीय विचार में डेयरी केवल उन जानवरों से होनी चाहिए जिन्हें रक्त युक्त पदार्थों वाला भोजन नहीं दिया जाता या जुगाली करने वाले अथवा सूअर के आंतरिक अंगों या ऊतकों से युक्त आहार नहीं दिया जाता है लेकिन अमेरिका का मानना है कि इस दृष्टिकोण में स्पष्ट पशु स्वास्थ्य या मानव स्वास्थ्य औचित्य का अभाव है। अब जब भारत ने एक खिड़की खोल दी है तो डेयरी के मामले में अमेरिकी दबाव दूर नहीं होगा बल्कि समय के साथ और बढ़ने की संभावना है।

इस आलोक में व्यापार समझौते में यह बयान कि, %भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए लंबे समय से चली आ रही गैर–टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए भी सहमत है, उस जाल की प्रकृति को इंगित करता है जिसमें भारत फंसता चला गया है। अमेरिका का एक विवादित बयान यह भी है कि भारत को छह महीने के भीतर यह निर्धारित करना होगा कि %सकारात्मक परिणाम की दृष्टि से ... क्या पहचाने गए क्षेत्रों में भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले अमेरिकी निर्यात के प्रयोजनों के लिए अमेरिका–विकसित या अंतरराष्ट्रीय मानक, परीक्षण आवश्यकताओं सहित स्वीकार्य हैं?

भारत पर टैरिफ कम करने के लिए ट्र प द्वारा जारी कार्यकारी आदेश (%रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों को संबोधित करने के लिए कर्तव्यों में संशोधन) एक समिति भी स्थापित करती है जो %इस बात की निगरानी करेगी कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ के तेल का आयात फिर से शुरू करता है या नहीं और दंडात्मक शुल्क वापस आने की धमकी के साथ यह निर्धारित किया जाता है कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया है या फिर से शुरू नहीं किया है।

इनमें से कोई भी शर्त भारत के लिए सहज नहीं है। समझौते का बचाव करने के लिए निश्चित रूप से सरकार आक्रामक हो गई है लेकिन यह संभावना नहीं है कि देश इन शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करेगा। सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह इस सौदे का अधिक बचाव न करे, जैसा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की थी। समझदारी यह होगी कि जनता की राय विकसित होने के आलोक में कुछ पीछे हटने के लिए जगह छोड़ी जाए।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और निष्पक्षता का खत्म होना

एन अशोक

लोकसभा अध्यक्ष का पद सिर्फ बहुमत पर नहीं, बल्कि भरोसे पर चलता है। अगर विपक्ष को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो एक काम करने वाली विधायिका के लिए ज़रूरी %पारस्परिक भरोसे% की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। जब सदन दोबारा शुरू होता है, तो हथौड़ा अभी भी डेस्क पर लग सकता है, लेकिन उससे जो आवाज़ आती है वह और ज़्यादा खोखली होती जाती है। भारत के संसद, जो लंबे समय से ज़ोरदार बहस और कभी–कभी हंगामे का मैदान रहा है, अब एक ऐसे युद्ध के मैदान में बदल गया है जहां निष्पक्ष अंपायर की अवधारणा ही खतरे में है। हाल ही में लगभग 120 विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास पेश करना सिर्फ एक प्रक्रिया से जुड़ी झड़प नहीं है, बल्कि यह एक ढांचागत दरार है। लोकसभा अध्यक्ष के इस दावे, जैसा पहले कभी नहीं हुआ,से शुरू हुए विवाद कि गुप्तचर सूचना से पता चला है कि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को %घेरने% की योजना बना रहे थे, स्वयं में एक ऐसी घटना है जो कार्यपालिका की सुरक्षा, विधायिका के विशेषाधिकार, और संसदीय स्वतंत्रता के क्रमबद्ध तरीके से खत्म होने के खतरनाक मेल को उजागर करती है।

इस संसदीय तूफान के केन्द्र में एक ऐसा दावा है जो एक ऐसे परिकल्पित राज्य या समाज की ओर इंगित करता है जहां लोग अन्याय से पीड़ित हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला का यह सार्वजनिक दावा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की रुकावट डालने वाली चालों की वजह से प्रधानमंत्री का सदन से गैरहाजिर रहना ज़रूरी हो गया था, भारतीय विधायिका के इतिहास में एक अहम मोड़ है। पर परा से लोकसभा अध्यक्ष सदन के अभिभावक होते हैं, जो कार्यपालिका के दखल से सांसदों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक ज़रूरी बहस से प्रधानमंत्री के गैरहाजिर रहने को सही ठहराने के लिए गुप्तचर सूचना का हवाला देकर, लोकसभा अध्यक्ष ने असल में पटकथा को पलट दिया है। वह सांसदों के रक्षक से सरकार की ढाल बन गए हैं।

नज़ारा कड़वा है– पीठासीन अधिकारी, जिसे सदन के अंदर आखिरी अधिकारी होना चाहिए, अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिचौलिए के तौर पर काम कर रहे हैं। इस कदम से पता चलता है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) और इंटेलिजेंस ब्यूरो अब स्पीकर की कुर्सी पर एक प्रॉक्सी सीट रखते हैं। अगर प्रधानमंत्री, जो देश के सबसे ताकतवर आदमी हैं, देश के सबसे सुरक्षित भवन के अंदर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों का सामना नहीं कर सकते, तो यह या तो सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी का इशारा है या एक आसान राजनीतिक पलायन की रणनीति का।

इस विवाद को और ज़्यादा ज़हरीला बनाया गुमनाम एप्सटीन फाइलों के वायरल होने ने, जिसमें विपक्ष के सांसदों को जोड़ा गया था, जो अजीब कपड़े फाड़ने की साज़िश थी। हालांकि सरकार ने इन्हें एआई से बनी चालें कहकर खारिज कर दिया, लेकिन असली नुकसान संस्थागत ताने–बाने को हुआ। जब लोकसभा अध्यक्ष की आधिकारिक बातें इंटरनेट पर टांग खींचने वाले सनसनीखेज बातों जैसी होती हैं– यह इशारा करते हुए कि महिला सांसद सुरक्षा के लिए खतरा हैं– तो सदन की इज़्ज़त न सिर्फ़ कम होती है; बल्कि वह जलकर राख हो जाती है।

संसदीय विरोध को एक शारीरिक खतरे के तौर पर दिखाकर, सत्ताधारी सरकार, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के ज़रिए, विपक्ष के असली मतलब को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में, %घेराव%, नारे लगाना और वॉकआउट उन लोगों के हथियार हैं जिन्हें वोट नहीं दिया जाता। इन पर %कानून व्यवस्था के जोखिम% के तौर पर छाप लगाना संसद को साफ–सुथरा बनाने और इसे एक एकल संस्कृति की गूंज वाले सदन में बदलने की एक सोची–समझी चाल है, जहां कार्यपालिका को कभी असहजता महसूस न हो। लोकसभा अध्यक्ष के कामों का तकनीकी बचाव अक्सर संविधान की चुप्पी में चला जाता है। जबकि अनुच्छेद 118 सदन को अपने नियम बनाने की इजाज़त देता है, ऐसा कोई साफ़ प्रावधान नहीं है जो लोकसभा अध्यक्ष को %गुप्तचर सूचना% के आधार पर प्रधानमंत्री को सत्र छोड़ने की सलाह देने का अधिकार दे। यह एक अस्पष्ट संवैधानिक ग्रे ज़ोन में आता है।

हालांकि, संवैधानिक नैतिकता सिर्फ़ लिखी हुई बातों के बारे में नहीं है, बल्कि जो व्यवहार में किया जाता है, उसके बारे में है। लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार निष्पक्षता की सोच पर टिका होता है। जब उस सोच को पार्टी की सुविधा के लिए बदल दिया जाता है, तो यह पद अपना नैतिक वजन खो देता है।

विपक्ष की शिकायत साफ़ है = अगर लोकसभा अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से गुप्तचर कथा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वे रेफरी नहीं रह जाते और प्लेयर बन जाते हैं। कार्यपालिका से परहेज का यह सामान्यीकरण यह पक्का करता है कि जि मेदारी विधायिका का मु य काम है, और वही सबसे पहले नुकसान में है। कुल 120 सांसदों के समर्थन वाला यह प्रस्ताव सं या के हिसाब से मजबूत नहीं है। भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए आराम से 272 का आंकड़ा पार कर जाएगा, इसलिए प्रस्ताव हार जाएगा, और ओम बिड़ला पद पर बने रहेंगे। तब विपक्ष को कैसे परेशानी होगी, यह सवाल खड़ा होता है। इसका जवाब भरोसे के बैरोमीटर में है। यह प्रस्ताव टूटे हुए रिश्ते का एक औपचारिक रिकॉर्ड है। राहुल गांधी के हस्ताक्षर की रणनीतिगत गैरमौजूदगी भी– शायद टकराव को सीधे %व्यक्तिगत% करने से बचने की एक चाल है– जो इस बात को नहीं छिपा सकती कि सदन का एक बड़ा हिस्सा अब अध्यक्ष को एक निष्पक्ष निर्णायक के तौर पर नहीं देखता। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास जो 1954 में जी.वी. मावलंकर से लेकर आज तक की है, एक रुझान दिखाती है– वह यह कि ये प्रस्ताव मोशन कभी भी वोट जीतने के बारे में नहीं होते; ये विश्वास के संकट को उजागर करने के बारे में होते हैं। ज़्यादा जानें समाचार संग्रह मोबाइल फोन ई–पेपर संसद के द्वार पर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का लोकसभा अध्यक्ष का फैसला एक किले जैसी विधानसभा की छवि को और मजबूत करता है। असहमति के लिए वास्तविक जगहों को बंद करके और सांसदों के व्यवहार पर शक जताने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करके, मौजूदा नेतृत्व भारतीय संसदीय राजनीति के डीएनए को पूरी तरह से बदल रही है। चुनावी कवरेज भाजपा का प्रति तर्क कि कांग्रेस ने पहले भी ऐसा ही बर्ताव किया था, अभी चल रही बढ़ती हुई बातों को नज़रंदाज़ करता है। अगर पिछले उदाहरण गलत थे, तो इसका हल पार्टीबाज़ी को दोगुना करना नहीं है, बल्कि उन %ऊंचे मानकों% को फिर से स्थापित करना है जिनकी एक उभरती हुई सुपरपावर को ज़रूरत है। 2026 का अविश्वास प्रस्ताव वोटों के मामले में शायद एक धीमी आवाज़ के साथ खत्म होगा, लेकिन इसकी गूंज बहरी कर देने वाली होगी। यह वह पल था जब दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के रेफरी पर न सिर्फ एक फ़ाउल मिस करने का आरोप लगा, बल्कि होम टीम की जर्सी पहनने का भी आरोप लगा। लोकसभा अध्यक्ष का पद सिर्फ बहुमत पर नहीं, बल्कि भरोसे पर चलता है। अगर विपक्ष को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो एक काम करने वाली विधायिका के लिए ज़रूरी %पारस्परिक भरोसे% की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। जब सदन दोबारा शुरू होता है, तो हथौड़ा अभी भी डेस्क पर लग सकता है, लेकिन उससे जो आवाज़ आती है वह और ज़्यादा खोखली होती जाती है। भारत की संसद अब सिर्फ बहस का घर नहीं रही; यह शक का घर है, जहां कार्यपालिका की सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल लोगों की आवाज़ दबाने के लिए किया जाता है।

विविध समाचार

बारिश से जहां मिली लोगों को राहत, वहीं जल जमाव एवं बिजली समस्या से लोग घंटो रहे परेशान

धमतरी। सोमवार की रात प्री–मानसून ने जिले में जोरदार दस्तक दी. दोपहर तक भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को शाम होते ही राहत मिली, लेकिन तेज बारिश ने नगर निगम और बिजली विभाग की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी. शाम करीब 6 बजे से शुरू हुई बारिश रात 10 बजे तक रुक–रुककर होती रही. इस दौरान कई बार बिजली कड़की और शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति बार–बार प्रभावित होती रही. मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

बारिश की वजह से आमापारा, ब्रह्मचौक, डबरीपारा, देवश्री टॉकीज रोड सहित कई प्रमुख मार्गों और निचली बस्तियों में पानी भर गया. बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित रही. कई स्थानों पर दोपहिया वाहन चालकों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों और दुकानों के सामने भी पानी भर गया, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें हुईं. तेज बारिश का असर यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिला. पुराने नेशनल हाईवे के कुछ हिस्सों में सड़क के ऊपर से पानी बहता नजर आया, जिसके कारण वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक आवागमन करना पड़ा. कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और यातायात प्रभावित

बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी बाधित हुई और सड़कें तालाब बन गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई के दावे किए जाते हैं।

लेकिन पहली ही बारिश में जलभराव की स्थिति ये बताती है कि जमीनी स्तर पर तैयारियां कितनी प्रभावी रहीं.बारिश के बाद शहरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने जलभराव और बदहाल सड़कों के वीडियो व तस्वीरें साझा करते हुए नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. कई लोगों ने टिप्पणी करते हुए कहा, ष्क्या मतलब करोड़ों की सड़कें बनाने का, जब मोहल्लों की दुर्दशा जस की तस बनी हुई है. कहीं भी भविष्य की योजना नजर नहीं आती, पहली बारिश में ही शहर पानी–पानी हो जाता ह

लोगों का आरोप है कि शहर में सड़कों और नालियों के निर्माण के दौरान दीर्घकालिक जल निकासी व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. कई वार्डों में वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है. वहीं बिजली विभाग की मेंटेनेंस व्यवस्था भी बारिश के दौरान कटघरे में नजर आई. तेज बारिश और बिजली कड़कने के बीच शहर के कई हिस्सों में बार–बार बिजली गुल होती रही. कहीं कुछ मिनटों के लिए तो कहीं घंटों तक बिजली गायब रही. नागरिकों ने सवाल उठाया कि यदि प्री–मानसून की पहली बारिश में ही बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है, तो पूरे मानसून सीजन में हालात और खराब हो सकते हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से पहले बिजली लाइनों के रखरखाव और पेड़ों की छंटाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश में ही बार–बार ट्रिपिंग और बिजली कटौती इन दावों की वास्तविकता उजागर कर देती है. बारिश थमने के बाद 1 से 2 घंटे के भीतर अधिकांश स्थानों पर स्थिति सामान्य होती भी दिखाई दी. सड़कों पर जमा पानी धीरे–धीरे निकल गया और यातायात भी सामान्य होने लगा.

पंढरपुर में श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ति के रासायनिक लेपन पर न्यायालय की तत्काल रोक

मंदिर महासंघ और वारकरी संगठनों की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला

पंढरपुर करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य देव पंढरपुर की श्री विठ्ठल–रुक्मिणी मूर्ति पर प्रस्तावित रासायनिक वज्रलेप पर पंढरपुर के दीवानी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति और पुरातत्व विभाग की ओर से 23 और 24 जून को यह लेपन प्रक्रिया की जाने वाली थी। इस निर्णय को चुनौती देते हुए वारकरी संप्रदाय, श्री. बालकृष्ण डिंगरे और महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के श्री. पुरुषोत्तम (गणेश) लंके ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्रीमती सोनाली राऊल ने प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के लेपन पर पाबंदी लगा दी है।

इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुधीर रानडे ने मूर्ति की पवित्रता और संरक्षण में मौजूद तकनीकी खामियों को लेकर न्यायालय में विस्तृत और प्रभावशाली दलीलें पेश कीं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया कि मूर्ति केवल एक पाषाण शिल्प नहीं है, बल्कि उसमें साक्षात देवत्व (प्राण) होता है और वह सजीव मानी जाती हैय इसलिए उस पर की जाने वाली कोई भी संरक्षण प्रक्रिया धर्मशास्त्र और पारंपरिक पद्धति के अनुसार ही होनी चाहिए। मंदिर समिति और पुरातत्व विभाग द्वारा श्इपॉक्सीश और अन्य कृत्रिम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके मूर्ति की दरारें भरने की संभावना थी। विशेष रूप से यह ध्यान में लाया गया कि इससे पहले चार बार किया गया रासायनिक लेपन विफल साबित होने के बावजूद प्रशासन उसी प्रक्रिया पर अड़ा हुआ है। कृत्रिम रसायनों के कारण पाषाण का प्राकृतिक श्वसन रुक जाता है, जिससे मूर्ति के अंदर से खोखली और नाजुक होने का गंभीर खतरा है।

इस कानूनी लड़ाई में उज्जैन के श्महाकालेश्वर मंदिरश मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का महत्वपूर्ण संदर्भ दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि प्रशासन को ऐसा कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है जिससे भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हों और परंपराओं का उल्लंघन हो। इसके साथ ही, करवीर पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा इस रासायनिक लेपन के स्पष्ट विरोध और तत्संबंधी आधिकारिक पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने इन सभी बातों का अत्यंत गंभीरता से संज्ञान लेते हुए लेपन पर रोक लगा दी।

इस निर्णय का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के राष्ट्रीय संगठक श्री. सुनील घनवट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगभग अट्ठाईस युगों से ईंट पर सुरक्षित खड़े पांडुरंग की मूर्ति के पैरों में कोरोना लॉकडाउन के दौरान गड्ढा कैसे पड़ गया और रुक्मिणी माता के पैर कैसे खराब हो गए, इसका कोई भी वैज्ञानिक और संतोषजनक उत्तर मंदिर समिति अब तक नहीं दे पाई है। जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुई बैठक में केवल राय दर्ज की गई, लेकिन वास्तविक संरक्षण प्रक्रिया में किन रसायनों का उपयोग किया जाएगा, इस पर प्रशासन ने अत्यधिक गोपनीयता बरती। अचानक प्रेस विज्ञप्ति निकालकर मंदिर बंद रखने का निर्णय घोषित करने से भक्तों में भारी भ्रम पैदा हो गया था। श्री. घनवट ने स्पष्ट किया कि रासायनिक लेपन के बजाय श्आयुर्वेदिक वज्रलेपश मूर्ति संरक्षण के लिए अधिक सुरक्षित और परंपरा के अनुरूप है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की है कि भविष्य में मंदिर समिति कोई भी एकतरफा निर्णय न लेते हुए वारकरी संप्रदाय, धर्माचार्यों और हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही कदम उठाएगी।

श्री. सुनील घनवट

आकाशीय बिजली से भेड़-बकरी की मृत्यु की घटना पर पशुधन विभाग की त्वरित कार्रवाई

धमतरी। विकासखंड मगरलोड के ग्राम डुमरपाली में विगत 17 जून रात्रि में आकाशीय बिजली गिरने से भेड़–बकरी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही पशुधन विकास विभाग की टीम द्वारा तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया। विभागीय अमले ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से चर्चा कर घटना की जानकारी प्राप्त की। जांच के दौरान ग्राम पंचायत डुमरपाली एवं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 40 भेड़–बकरियों की मृत्यु हुई थी। उक्त पशु अन्य राज्यों से आए घुमंतू चरवाहों के थे। घटना के बाद संबंधित चरवाहों द्वारा मृत पशुओं को गड्ढा खोदकर दफना दिया गया तथा वे वहां से अन्यत्र चले गए।पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने दफनाए गए स्थल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में वहां किसी प्रकार के संक्रमण अथवा पशुजनित बीमारी फैलने की स्थिति नहीं है। विभाग द्वारा आवश्यक सावधानियों के साथ स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। पशुधन विकास विभाग ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुई इस घटना के संबंध में उपलब्ध तथ्यों का संकलन कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ अग्निकांड: व्यावसायिक इमारत के मालिक का आपराधिक इतिहास

लखनऊ। लखनऊ के अलीगंज में जिस 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई है, उसके मालिक का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। इमारत के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुज़्ला हैं और सह–मालिक सुरेंद्र शुज़्ला हैं। सुरेंद्र का नाम 2015 में संयुक्त प्री–मेडिकल टेस्ट (सीपीएमटी) पेपर लीक से जुड़ा हुआ है।

बाघिन के विडियो और फोटो से उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के पुनरूथान की जगी नई उम्मीद

गरियाबंद-धमतरी : उदंती -सीतानदी टाइगर के लिए हाल ही में एक अत्यंत उत्साहजनक और ऐतिहासिक खबर सामने आई है. हाल के दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में लगे कैमरा ट्रैप से प्राप्त वीडियो और तस्वीरों ने एक बाघिन की नियमित उपस्थिति की पुष्टि की है. जो संभवत: प्राकृतिक रूप से विचरण करते हुए उदंती सीतानदी के वनों में पहुंची है और अब इस क्षेत्र को अपना नया घर बना रही है. लंबे समय से बाघों की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे उदंती सीतानदी के लिए इस बाघिन का आगमन मात्र एक वन्यजीव दृश्य नहीं, बल्कि पूरे परिदृश्य के पुनर्जीवन का संकेत और नई आशा की किरण है. स्वस्थ एवं आत्मविश्वास से अपने क्षेत्र में विचरण करती इस बाघिन की गतिविधियां इस बात का संकेत देती है कि वह यहां अपना क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है. पिछले कुछ वर्षों से उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में आवास सुधार एवं संरक्षण की दिशा में व्यापक प्रयास किए गये हैं. इनमें सुदृढ गश्त एवं एंटी पोचिंग व्यवस्था सैकड़ों कृत्रि जल स्त्रोतों एवं झिरियाओं का निर्माण क्षतिगस्त वन क्षेत्रों का पुनर्स्थापना अतिक्रमण हटाकर वन भूमि की पुनर्प्राप्ति एवं वन जीवों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल आवास का निर्माण शामिल है. बाघिन की प्राकृतिक उपस्थिति इन प्रयासों की सफलता का सकारात्मक संकेत है.

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व को लौटाई उसकी खोई हुई जैव विविधता

गरियाबंद–धमतरी। उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी. एन. गोदावर्मन जनहित याचिका क्रमांक 202ध1995 में दिनांक 17 नवम्बर 2025 को दिए गए उस ऐतिहासिक निर्णय का हृदय से स्वागत एवं आभार व्यक्त किया है, जिसके अंतर्गत देशभर के टाइगर रिजर्वों के कोर क्षेत्रों में रात्रिकालीन यातायात पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2025 में इस निर्णय को लागू करने के पश्चात उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में इसके अत्यंत सकारात्मक पारिस्थितिक परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व के दो कोर क्षेत्रों दृ उदंती कोर एवं सीतानदी कोर दृ से क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग छभ–130ढ और छभ–130ब्ब होकर गुजरते हैं। वर्षों तक इन सड़कों पर रात्रिकालीन यातायात के कारण जंगल की छत्राकार वृक्ष संरचना खंडित होती रही, जिससे वृक्षों की ऊपरी परत पर निर्भर रहने वाली दुर्लभ गिलहरियों की प्राकृतिक आवाजाही प्रभावित होती थ

उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले भारतीय विशाल उड़न गिलहरी तथा भारतीय विशाल गिलहरी जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ अपना अधिकांश जीवन वृक्षों की ऊपरी परतों में बिताती हैं और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक छलांग अथवा ग्लाइड करके ही संचरण करती हैं। ये प्रजातियाँ वन की अखंड छत्राकार संरचना की सर्वश्रेष्ठ जैव–सूचक मानी जाती हैं तथा आवास विखंडन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं।रात्रिकालीन यातायात बंद होने के पश्चात इन दुर्लभ वृक्षवासी प्रजातियों का विस्तार अब उदंती एवं सीतानदी कोर क्षेत्रों से आगे बढ़कर रिसगांव (कोर), इंदागांव (बफर), आरसीकन्हार (बफर) तथा कुल्हाड़ीघाट (बफर) क्षेत्रों तक दर्ज किया जा रहा है। यह विस्तार इस बात का संकेत है कि टाइगर रिजर्व की पारिस्थितिक गुणवत्ता एवं वृक्षीय संपर्कता पुनर्जीवित हो रही है।

सुमीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने १९९.७५ करोड़ के राइट्स इश्यू की घोषणा की

रांची, पॉलिएस्टर टेक्सचराइज्ड यार्न, पार्टियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई), फुली ड्रॉन यार्न (एफडीवाई) के उत्पादन से जुड़े अग्रणी एकीकृत पॉलिएस्टर निर्माताओं में से एक, सुमीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएसईरू 514211) ने अपने पात्र शेयरधारकों के लिए राइट्स इश्यू की घोषणा की है।

इसका उद्देश्य कंपनी की वित्तीय लचीलापन बढ़ाना तथा उसकी रणनीतिक व्यावसायिक प्राथमिकताओं को समर्थन प्रदान करना है। सुमीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयर जारी करके कुल रू. 199.75 करोड़ के राइट्स इश्यू की शर्तों को मंजूरी प्रदान की है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, बुधवार 26 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

आरएसपी ने सभी विभागों में मेरा क्षेत्र, मेरी जिमेदारी सुरक्षा ऐप का विस्तार किया

राउरकेला २५/०८ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आर.एस.पी.), सेल ने अपनी सुरक्षा संस्कृति को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मेरा क्षेत्र, मेरी जिमेदारी सुरक्षा ऐप का विस्तार संयंत्र के सभी विभागों में कर दिया है। इस ऐप को सी. एंड आई.टी. तथा डिजिटलीकरण विभागों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप को प्रारंभ में न्यू प्लेट मिल (एन.पी.एम.) विभाग में सुरक्षा संबंधी अवलोकनों और असुरक्षित स्थितियों की आसानी से रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित एवं लागू किया गया था। इसके सफल कार्यान्वकयन के बाद अब इस पहल का विस्तार आर.एस.पी. के सभी विभागों में कर दिया गया है। ऐप के संबंध में परिचयात्मक कार्यक्रम का

आयोजन 21 अगस्त 2026 को समागम सज्मेलन कक्ष में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुज़्यो महा प्रबंधक (एन.पी.एम. एवं डिजिटलीकरण), श्री आर.के.मुदुली ने की। इस अवसर पर मुज़्यल महा प्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं), श्री हीरालाल महापात्र, विभागाध्यक्ष (सुरक्षा विभाग), श्री अवकाश बेहेरा तथा महा प्रबंधक प्रभारी (सी. एंड आई.टी.), श्रीमती सुमिता भट्टाचार्य, भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का मुज़्य उद्देश्य विभागीय प्रतिनिधियों के बीच ऐप की विशेषताओं एवं इसके उपयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना था। साथ ही, सुरक्षा संबंधी अवलोकनों की रिपोर्टिंग और उनके समयबद्ध निराकरण में अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

इस ऐप की संकल्पना एवं विकास उप महा प्रबंधक (सी. एंड आई.टी.), श्री वी.पी.आर्या तथा सहायक प्रबंधक (डिजिटलीकरण), श्री अभिषेक बेहेरा ने श्रीमती भट्टाचार्य एवं श्री मुदुली के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किया गया है।

ऐप को डाउनलोड करने और एज़्सेस करने के लिए ज़्यू.आर. कोड आर.एस.पी. पोर्टल पर उपलज़्ध कराया जाएगा, जिससे संयंत्र के कर्मचारी सुरक्षा संबंधी अवलोकनों की रिपोर्टिंग के लिए आसानी से ऐप का उपयोग कर सकेंगे। यह पहल सुरक्षा प्रबंधन में कागजरहित एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। इस ऐप का विस्तार आर.एस.पी. की सक्रिय सुरक्षा, कर्मचारी सहभागिता और कार्यस्थल की सुरक्षा के प्रति स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सरल किंतु प्रभावशाली सिद्धांत को और मजबूत करता है - मेरा क्षेत्र, मेरी जिमेदारी

श्याम सुंदर चांदीवाला ने भुवनेश्वर में खोला नया शोरूम

भुवनेश्वर २५/०८ (संवाददाता): प्रसिद्ध सिल्वर ब्रांड श्याम सुंदर चांदीवाला 26 अगस्त 2026 को भुवनेश्वर में अपने नए शोरूम का शुभारंभ करेगा। यह ओडिशा में ब्रांड का पहला और देशभर में 18वां शोरूम होगा। कानन विहार, पटिया स्थित नए शोरूम में हॉलमार्क सिल्वर की विस्तृत रेंज उपलज़्ध होगी, जिसमें सिल्वर ज्वेलरी, बर्तन, देवी-देवताओं की प्रतिमाएं और गिफ़्ट आइटम शामिल हैं। ब्रांड अपनी पहचान The Shine of Purity के साथ शुद्धता, पारदर्शिता और भरोसे के लिए जाना जाता है। संस्थापक श्री सुंदर भालोटिया ने कहा कि भुवनेश्वर में पहला शोरूम खोलना ब्रांड के लिए गौरवपूर्ण उपलज़्धि है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के भरोसे और सहयोग से श्याम सुंदर चांदीवाला लगातार देशभर में विस्तार कर रहा है। आने वाले समय में कई और नए शोरूम खोलने की योजना है।

कांग्रेस ने माइनिंग बिल पर मांगा विधानसभा का विशेष सत्र, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

भुवनेश्वर २५/०८ (संवाददाता): कांग्रेस की ओडिशा इकाई ने 'खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक' पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून से राज्य की शक्तियां कम हो जाएंगी और भारी राजस्व का नुकसान होगा। राम चंद्र कदम के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे सदन का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया।

कदम ने संवाददाताओं से कहा, "हमने राज्यपाल को खनन से जुड़े नए विधेयक के प्रति अपने विरोध के बारे में बताया और इसे वापस लेने की मांग की। हमने उनसे इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाने का भी आग्रह किया।" उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के दोनों सदनों ने बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में यह विधेयक पारित किया। कदम ने इस विधेयक को 'काला कानून' करार देते हुए दावा किया कि इसका उद्देश्य खनिज अधिकार और खनिज वाली भूमि पर कर लगाने की राज्य की शक्तियों को सीमित करना और संघीय ढांचे को कमज़ोर करना है।

उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन की वजह से ओडिशा को लगभग एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है और सालाना राजस्व में करीब 20,000 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा कि इन संशोधनों से लाखों लोगों, खासकर आदिवासी समुदायों के हितों को गंभीर खतरा है और इससे राज्य की विज़्तीय स्वायज़्तता सीमित हो जाएगी। इससे पहले, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने नए खनन कानून का विरोध किया और लोगों से अपने उन अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की।

उन्होंने दावा किया कि लोगों के अधिकार केंद्र द्वारा छीने जा रहे हैं। सज़्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हालांकि विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कांग्रेस तथा बीजू जनता दल (बीजद) पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा महासचिव बिरंची नारायण त्रिपाठी ने कहा, "ओडिशा समेत सभी खनिज-समृद्ध राज्यों और सबसे बढ़कर पूरे देश को इस नए कानून से लाभ होगा।

सांप के काटने से 5 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, मंत्री ने दिए निर्देश

भुवनेश्वर २५/०८ (संवाददाता): सुंदरगढ़, राउरकेला, भद्रक और बालासोर जिलों में कथित तौर पर जहरीले सांप के काटने से एक बुजुर्ग और पांच नाबालिगों की जान चली गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने पीड़ितों को तुरंत विषरोधी उपचार मुहैया कराने की अपील की है।

ओडिशा में अलग-अलग घटनाओं में संदिग्ध सर्पदंश से पांच नाबालिगों समेत छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सुंदरगढ़ के तिलाईमाल गांव में सोमवार रात घर के फर्श पर सो रहे 76 वर्षीय एक व्यक्ति और उनके आठ वर्षीय पोते को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रबि भुइयां और उनके पोते संजय नायक के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि राउरकेला शहर के रघुनाथपाली थाना क्षेत्र में भी संदिग्ध सर्पदंश से दो नाबालिग भाई-बहन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान 10 वर्षीय समीर हारो और उसकी सात वर्षीय बहन साइरेन हारो के रूप में हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भद्रक के चंदबली इलाके में 10 वर्षीय एक बच्ची और बालासोर के बालीपाल इलाके की एक अन्य बच्ची की भी संदिग्ध सर्पदंश से मौत हो गई। ओडिशा के कुछ हिस्सों में बाढ़ के बीच ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा, "लोगों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सांप के काटने के एक घंटे के भीतर पीड़ित को विषरोधी उपचार मिल जाए।

रिटायर्ड एग्जीज़्यूटिव इंजीनियर की 2.50 करोड़ रुपये की संपज़ि जज़्त

भुवनेश्वर २५/०८ (संवाददाता): यहां की एक ज़ज़्ती कोर्ट ने मंगलवार को एक रिटायर्ड एग्जीज़्यूटिव इंजीनियर की 2.50 करोड़ रुपये की आय से ज़्यादा संपज़ि ज़ज़्त करने का आदेश दिया। यह आदेश विजिलेंस केस में दोषी पाए जाने के बाद दिया गया। ज़ज़्ती कोर्ट (ऑथराइज़्ड ऑफिसर, स्पेशल कोर्ट, विजिलेंस, भुवनेश्वर) ने नबरंगपुर ज़िले के उमरकोट में R.W. डिवीज़न के पूर्व एग्जीज़्यूटिव इंजीनियर (रिटायर्ड) सिमाद्री नायक की 2,50,44,029 रुपये की संपज़ि ज़ज़्त करने का आदेश दिया। इन संपज़ियों में चल और अचल दोनों तरह की संपज़ियां शामिल हैं। अचल संपज़ियों में रायगढ़ में एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग, नबरंगपुर में दो बिल्डिंग और ज़मीन के तीन प्लॉट शामिल हैं — एक रायगढ़ शहर में और दो नबरंगपुर शहर में। चल संपज़ियों में बैंक डिपॉज़िट और सोने के गहने शामिल हैं।

ओडिशा विजिलेंस की तरफ से जारी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, नायक और उनकी पत्नी पर प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एज़्ट, 1988 के सेज़्शन 13(2) के साथ 13(1)(द्) और ढ्ढक्क्ष्ट के सेज़्शन 109 के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। उन पर कथित तौर पर उनकी इनकम के जाने-पहचाने सोर्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने का आरोप था। ट्रायल के बाद, स्पेशल कोर्ट, भुवनेश्वर के स्पेशल जज ने 11 दिसंबर, 2023 को नायक और उनकी पत्नी को इनकम से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने का दोषी ठहराया। इसके बाद की कार्रवाई में तय कोर्ट ने ज़ज़्त करने का ऑर्डर पास किया। ओडिशा विजिलेंस की तरफ से जारी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, नायक और उनकी पत्नी पर प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एज़्ट, 1988 के सेज़्शन 13(2) के साथ 13(1)(द्) और ढ्ढक्क्ष्ट के सेज़्शन 109 के तहत चार्जशीट दायर की गई थी।

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिज़्यूनल से संपर्क करने का निर्देश दिया

कटक २५/०८ (संवाददाता): ओडिशा हाई कोर्ट ने झारसुगुड़ा जिले में नेशनल हाईवे नंबर 49 के निर्माण के दौरान फ़्लाई ऐश को बिना किसी नियम के डंप करने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के आरोप वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिज़्यूनल के सामने समाधान खोजने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एमएस रमन की डिवीजन बेंच सुमंता स्वैन और आठ अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में फ़्लाई ऐश को अंधाधुंध तरीके से डंप करने के कारण हवा और पानी के प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई गई थी, जिससे याचिकाकर्ताओं के अनुसार, फसलों को नुकसान हुआ, तालाब और भूजल दूषित हुआ, मछलियां मरीं, और आस-पास के गांवों में सिंचाई और मछली पालन प्रभावित

हुआ बेंच ने शुरू में ही सवाल किया कि याचिकाकर्ताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिज़्यूनल एज़्ट, 2010 के तहत उपलज़्ध कानूनी उपाय का इस्तेमाल करने का निर्देश ज़्यों नहीं दिया जाना चाहिए। आरोपों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने ऐसे मामलों में न्यायिक अनुशासन पर जोर दिया जहां विशेष फोरम मौजूद हैं। बेंच ने कहा, इस रिट याचिका में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे फ़्लाई ऐश को बिना किसी नियम के डंप करने से पर्यावरण में प्रदूषण और आस-पास के लोगों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान से संबंधित हैं, साथ ही सिंचाई और मछली पालन के लिए इस्तेमाल होने वाले तालाबों और भूजल के दूषित होने का भी जिक्र किया।

नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर संगोष्ठी की गई आयोजित

राउरकेला २५/०८ (संवाददाता): आईजीएच, राउरकेला के नर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनटीआई) में मनोरोग नर्सिंग पाठ्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी में एनटीआई के कुल 157 छात्रों ने भाग लिया।

इस संगोष्ठी का उद्देश्य नर्सिंग छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के प्रति जागरूक करना और इसके ज़िज़्मेदार व संतुलित इस्तेमाल के बारे में जानकारी बढ़ाना था। इस कार्यक्रम ने छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ वे सोशल मीडिया के अत्यधिक या गलत इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी नतीजों, साथ ही भावनात्मक सेहत और आपसी रिश्तों पर इसके असर को समझ सकें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के सलाहकार डॉ. देबाशीष मोहंता ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की, जबकि एनटीआई की प्रिंसिपल श्रीमती विद्युत प्रभा गोथ भी इस अवसर पर मौजूद थीं।

कार्यक्रम की शुरुआत जीएनएम तीसरे वर्ष के छात्र श्री कौशिक कुमार घोष के उद्घाटन भाषण से हुई। जीएनएम तीसरे वर्ष के चार छात्रों — मिस ज्योतिरेखा स्वाइन, श्री हर्षवर्धन बेहरा, मिस जिनीता मोहंता और मिस स्मितारानी एक्का — ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद एक इंटरैज़्टिव चर्चा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को अपने दृष्टिकोण साझा करने और मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण और पारस्परिक संबंधों पर सोशल मीडिया के प्रभावों पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। अकादमिक सत्र का समापन एनटीआई की वाइस-प्रिंसिपल श्रीमती नबनिता जेना के समापन भाषण के साथ हुआ।

कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर महिला को धोखा दिया

केंद्रपाड़ा २५/०८ (संवाददाता): एक 30 साल के पुलिस कांस्टेबल को शनिवार को शादी का झांसा देकर एक महिला का एक साल से ज़्यादा समय तक यौन शोषण करने के आरोप में गिरज़्तार किया गया।

आरोपी का नाम श्रुतिरंजन खुंटिया है, जो तांतियापाला मरीन पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है। 23 साल की शिकायतकर्ता के अनुसार, खुंटिया ने शादी का वादा करके पिछले एक साल में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और जब उसने उस पर शादी करने का दबाव डाला, तो उसने कथित तौर पर उसे धमकी देना शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया कि बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि खुंटिया शादीशुदा है और उसका फायदा उठा रहा है। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी को क्क्रस्र की संबंधित धाराओं के तहत गिरज़्तार किया।केंद्रपाड़ा टाउन ढ्ढढ्ढष्ट दिलीप साहू ने कहा कि खुंटिया को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा, शिकायतकर्ता का केंद्रपाड़ा जिला मुज़्यालय अस्पताल में मेडिकल जांच की गई और उसके बयान दर्ज किए गए हैं।

AFFIDAVIT

I, SANGEETA PANIGRAHI, aged about 64 years, W/o SANATANA PANIGRAHI, resident of Plot No.L/121, Phase-I, Chhend, P.O. Rourkela, P.S. Chhend, Dist: Sundargarh, Odisha-769015, declare by this affidavit No. A/79, dtd. 24.08.26, that now onwards I shall be known as SANGEETA PADHI for all future purposes.